IIPDF योजना

प्रिलिम्स के लिये:

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना (IIPDF योजना), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT), बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO), बिल्ड-ऑपरेट-लीज़-ट्रांसफर (BOLT), डिज़ाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT), लीज़-डेवलप-ऑपरेट (LDO), ऑपरेट-मेंटेन-ट्रांसफर (OMT)।

मेन्स के लिये:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी का समर्थन करने के लिये पहल और विकास योजनाएँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), **वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिये वित्तीय सहायता हेतु भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना (IIPDF योजना) को अधिसूचित किया।**

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना (IIPDF योजना):

- **परिचय:**
    - **IIPDF योजना की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी।**
    - यह वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तीन साल की अवधि के लिये 150 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।**
    - यह परियोजना विकास लागत को पूरा करने के लिये **PPP परियोजनाओं के प्रायोजक प्राधिकरणों के लिये उपलब्ध है।**
        - PPP परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने और **बड़े नीति एवं नियामक मुद्दों को संबोधित करने के लिये PPP सेल का निर्माण तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रायोजक प्राधिकरण के लिये यह आवश्यक होगा।**
- **उद्देश्य:**
    - **इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण परियोजना विकास गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।**
- **महत्त्व:**
    - प्रायोजक प्राधिकरण, PPP लेन-देन लागत के एक हिस्से को कवर करने के लिये वित्तपोषण के स्रोत के रूप में सक्षम होगा **जिससे उनके बजट पर खरीद से संबंधित लागतों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।**
- **वित्तीय परिव्यय:**
    - IIPDF **परियोजना विकास खर्च का 75% तक प्रायोजक प्राधिकरण को ब्याज़ मुक्त ऋण के रूप में योगदान देगा।** शेष 25% प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सह-वित्तपोषित किया जाएगा।
    - बोली प्रक्रिया के सफल समापन पर **सफल बोलीदाता से परियोजना विकास व्यय की वसूली की जाएगी।**
    - हालाँकि बोली की विफलता के मामले में ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।
    - यदि प्रायोजक प्राधिकरण किसी कारण से बोली प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, **तो योगदान की गई पूरी राशि IIPDF को वापस कर दी जाएगी।**

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के प्रकार:

- **बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT)**: यह एक **पारंपरिक PPP मॉडल** है जिसमें निजी भागीदार डिज़ाइन, निर्माण, संचालन (अनुबंधित अवधि के दौरान) और सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र में वापस स्थानांतरित करने के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
    - निजी क्षेत्र के भागीदार को किसी परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था करनी होती है और इसके निर्माण एवं रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी होती है।
    - सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के भागीदारों को उपयोगकर्त्ताओं से राजस्व एकत्र करने की अनुमति देगा। PPP मोड के तहत NHAI

द्वारा अनुबंधति राष्ट्रीय राजमार्ग परयिोजनाएँ BOT मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण है।

- **बलि्ड-ओन-ऑपरेट (BOO)**: इस मॉडल में नवनरि्मति सुवधिा का स्वामत्वि नजिी पार्टी के पास रहेगा।
    - पारस्परकि रूप से नयिमों और शर्तों पर सार्वजनकि क्षेत्र की भागीदार परयिोजना द्वारा उत्पादति वस्तुओं एवं सेवाओं की 'खरीद' करने पर सहमत बिनाई जाती है।
- **बलि्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT):** इसके अंतर्गत समय पर बातचीत के बाद परयिोजना को सरकार या नजिी ऑपरेटर को स्थानांतरति कर दयिा जाता है।
    - BOOT मॉडल का उपयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के वकिास के लयि कयिा जाता है।
- **बलि्ड-ऑपरेट-लीज़-ट्रांसफर (BOLT):** इस मॉडल में सरकार नजिी साझेदार को सुवधिाओं के नरि्माण, डज़िाइन, स्वामत्वि और लीज़ का अधकिार देती है तथा लीज़ अवधकि अंत में सुवधिा का स्वामत्वि सरकार को हस्तांतरति कयिा जाता है।
- **डज़िाइन-बलि्ड-फाइनेंस-ऑपरेट (DBFO):** इस मॉडल में अनुबंधति अवधकि लयि परयिोजना के डज़िाइन, उसके वनिरि्माण, वति्त और परचिालन का उत्तरदायति्व **नजिी साझीदार** पर होता है।
- **लीज़-डेवलप-ऑपरेट (LDO):** इस प्रकार के नविश मॉडल में **या तो सरकार या सार्वजनकि क्षेत्र के पास** नवनरि्मति बुनयिादी ढाँचे की सुवधिा का स्वामत्वि बरकरार रहता है और नजिी प्रमोटर के साथ लीज़ समझौते के रूप में भुगतान प्राप्त कयिा जाता है।
    - इसका पालन अधकितर एयरपोर्ट सुवधिाओं के वकिास में कयिा जाता है।
- **इंजीनयिरगि, खरीद और नरि्माण (EPC) मॉडल:** इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार नजिी कंपनयिों से इंजीनयिरगि कार्य के लयि बोलयिाँ आमंत्रति करती है। कच्चे माल की खरीद और नरि्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। नजिी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम तथा इंजीनयिरगि वशिेषज्ञता के प्रावधान तक सीमति होती है। इस मॉडल की एक समस्या यह है कि इससे सरकार पर वति्तीय बोझ बढ़ता है।
- **हाइब्रडि एन्युटी मॉडल (HAM):** भारत में नया HAM, **BOT-एन्युइटी और EPC मॉडल** का मशि्रण है। डज़िाइन के अनुसार, सरकार वार्षकि भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों में परयिोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष भुगतान सृजति परसिंपत्तयिों एवं**वकिासकर्ता के प्रदर्शन** के आधार पर कयिा जाएगा।

यूपीएससी सवििल सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. सार्वभौम अवसंरचना सुवधिा (ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलिटिी)- (2017)

(a) एशयिा में अवसंरचना के उन्नयन के लयि ASEAN का उपक्रमण है, जो एशयिाई वकिास बैंक द्वारा दयि गए साख (क्रेडटि) से वति्तपोषति है।
(b) गैर-सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत नविशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लयि वशि्व बैंक का सहयोग है, जो जटलि अवसंरचना सरकारी गैर-सरकारी भागीदारयिों (PPPs) की तैयारी और संरचना-नरि्माण को सुकर बनाना है।
(c) OECD के साथ कार्य करने वाले वशि्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, जो उन अवसंरचना परयिोजनाओं को वस्तिारति करने पर केंद्रति है जनिमें गैर-सरकारी वनिविश संग्रहण करने की क्षमता है।
(d) UNCTAD द्वारा वति्तपोषति उपक्रमण है जो वशि्व में अवसंरचना के वकिास को वति्तपोषति करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है।

उत्तर: B

व्याख्या:

- वर्ष 2014 में, वशि्व बैंक ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलिटिी (GIF) शुरू की, जो बहुपक्षीय वकिास बैंकों (MDBs), नजिी क्षेत्र के नविशकों और वति्तपोषकों, उभरते बाजारों और वकिासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) के बुनयिादी ढाँचे के नविश में रुचि रखने वालों के बीच सरकार के प्रयासों का सार्वजनकि-नजिी-भागीदारी के माध्यम से समन्वय और एकीकरण करती है।
- ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलिटिी (GIF) बुनयिादी ढाँचा परयिोजनाओ को अच्छी तरह से संरचति कर इसको संचालति करने में सरकारों की सहायता करता है। यह परयिोजना की डज़िाइन, तैयारी, संरचना, अंतरण और कार्यान्वयन गतविधियिों के स्पेक्ट्रम को कवर करती है, GIF के तकनीकी और सलाहकार भागीदार संयुक्त वशिेषज्ञता के आधार पर डज़िाइन और संरचना पर ध्यान केंद्रति करते हैं जो नजिी नविशकों की एक वस्तिृत शृंखला को आकर्षति कर सकती हैं।

अतः वकिल्प (b) सही उत्तर है।

??????:

प्रश्न: सार्वजनकि-नजिी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में हवाई अड्डों के वकिास का परीक्षण कीजयि। इस संबंध में अधकिारयिों के सामने क्या चुनौतयिाँ हैं? **(मुख्य परीक्षा, 2017)**

प्रश्न. ढाँचागत परयिोजनाओं में सार्वजनकि-नजिी भागीदारी (PPP) की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्वकिास में PPP मॉडल की भूमकिा का परीक्षण कीजयि। **(मुख्य परीक्षा, 2022)**

स्रोत:पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/iipdf-scheme